राजधानी
वर्ष 12 | अंक 90 | पृष्ठ : 18+8=26
मूल्य : चार रुपये या पांच रुपये उड़ान सहित
7 राज्य • 1 केंद्रशासित प्रदेश • 21 संस्करण

अमर उजाला

लखनऊ
बुधवार, 25 सितंबर 2019

आज उड़ान

मेरठ। चौधरी चरण सिंह विवि द्वारा एमपीएड पाठ्यक्रम में 2019-20 की प्रवेश सूची में स्थान पाने वाले छात्रों के नाम जारी कर दिए गए हैं।

वर्ष 2022 तक 50% कोर्स का एनबीए नहीं तो कॉलेज भी होंगे बंद

एआईसीटीई के नवनियुक्त सदस्य सचिव राजीव कुमार बोले, सीटों में भी होगी कटौती

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने तकनीकी शिक्षा से जुड़े कोर्सों के नेशनल बोर्ड एक्रीडिएशन (एनबीए) पर सख्ती शुरू कर दी है। एक कार्यक्रम में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) पहुंचे एआईसीटीई के नवनियुक्त सदस्य सचिव प्रो. राजीव कुमार ने कहा कि वर्ष 2022 तक अगर 50 फीसदी कोर्स का एनबीए नहीं कराया तो संबंधित कोर्स व कॉलेज बंद किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि अगर कोर्स की जरूरत के अनुसार शिक्षक, लैब, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट आदि की व्यवस्था नहीं होगी तो विद्यार्थी क्या पढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हम एनबीए कराने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित भी करेंगे। वर्तमान में देश में लगभग 35 हजार इंजीनियरिंग संस्थान हैं। इनमें से महज 17 फीसदी कॉलेजों ने ही एनबीए कराया है। क्योंकि ज्यादातर कॉलेज इसके मानक पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ये हर साल 7-8 लाख इंजीनियर पैदा कर रहे हैं। अगर यह क्वालिटी इंजीनियर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? ये कहां जाएंगे, इन्हें कहां रोजगार मिलेगा। भविष्य इन चीजों को ध्यान में रखकर ही संस्थानों को मान्यता दी जाएगी।

कुवैत में 15 हजार भारतीय इंजीनियरों पर आया संकट : प्रो. कुमार ने कहा कि पिछले दिनों कुवैत सरकार ने वहां काम कर रहे 15 हजार भारतीय इंजीनियरों का वर्क परमिट रिन्यू नहीं किया। बताया गया कि उनकी डिग्री एक्रीडिएट इंस्टीट्यूट की नहीं था। इस पर भारत सरकार ने हस्तक्षेप कर उनका परमिट रिन्यू कराया। भविष्य यह समस्या किसी और देश में हो सकती है। ऐसे में एनबीए जरूरी है। एनबीए कराने वाले संस्थानों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और डिग्री में भी इसका उल्लेख होगा।

प्रो. राजीव कुमार

17%

इंजीनियरिंग संस्थानों ने ही कराया एनबीए

1.50 लाख सीटें कम की, फार्मेसी में नई संबद्धता नहीं

प्रो. कुमार ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के तहत इस साल इंजीनियरिंग में 1.50 लाख सीटें कम की गई हैं। एमबीए-पीजीडीएम में ज्यादा सीटें कम हुई हैं। इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी की काफी मान्यता हुई है, किंतु अगले दो साल तक फार्मेसी में नई संबद्धता नहीं देने का निर्णय लिया गया है। वहीं, फार्मेसी काउंसिल ने पांच साल तक रोक लगाई है।

परीक्षा सुधार में तकनीक की भूमिका अहम

लखनऊ। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के नवनियुक्त सदस्य सचिव प्रो. राजीव कुमार ने कहा कि तकनीक ने हर विधा में गैप बना दिया है। टीचिंग-लर्निंग के साथ परीक्षा प्रणाली में भी सुधार की जरूरत है। इसमें तकनीक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वे एकेटीयू में परीक्षा सुधार से संबंधित कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एकेटीयू ने इस दिशा में काफी काम किया है। यहां डिजिटल मूल्यांकन, ऑनलाइन पेपर डिलीवरी का काम हो रहा है। विवि जल्द ही ई-ऑफिस की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। यह सराहनीय प्रयास है। एकेटीयू कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने कहा कि तकनीक से परीक्षा और परिणामों में एक्यूरेसी बढ़ रही है। रिकॉर्ड संरक्षित करने में डिजिटल मोड काफी सुरक्षित है। डिजी लॉकर से प्रमाण पत्रों की उपलब्धता और प्रामाणिकता मात्र एक क्लिक तक सीमित हो गई है। कार्यशाला में केएलई तकनीकी विवि हुबली के डॉ. पीजी तिवारी, प्रो. गोपाल कृष्णन, एआईसीटीई के रीजनल ऑफिसर डॉ. मनोज कुमार, रजिस्ट्रार नंदलाल सिंह, प्रति कुलपति प्रो. विनीत कंसल, परीक्षा नियंत्रक प्रो. राजीव कुमार व अपर परीक्षा नियंत्रक डॉ. अनुराग त्रिपाठी भी शामिल हुए। ब्यूरो

इंजीनियरिंग में सवालों के जवाब क्यों व कैसे में देने होंगे

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। एआईसीटीई ने एग्जाम रिफार्म पॉलिसी को लेकर कवायद तेज कर दी है। इस क्रम में एआईसीटीई ने इंजीनियरिंग के पेपर में से क्या हुआ, कब हुआ और व्याख्या करें, जैसे शब्दों पर सख्ती से रोक लगाई है। वहीं, अब विद्यार्थियों को क्यों हुआ, कैसे हुआ और कैसे होगा, में प्रश्नों के जवाब देने होंगे। इंजीनियरिंग के पेपर से अब रटने वाले सवाल हटेंगे और नए एप्लीकेशन, एनालिटिकल व क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित प्रश्न जोड़े जाएंगे। यह जानकारी एकेटीयू में शिक्षकों को एग्जाम रिफार्म पॉलिसी की ट्रेनिंग देने आए एआईसीटीई के सदस्य सचिव प्रो. राजीव कुमार ने अनौपचारिक बातचीत में दी।

एआईसीटीई ने एग्जाम रिफॉर्म पॉलिसी पर विश्वविद्यालयों में तेज की कवायद

इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए अभी कॉमन प्लेटफार्म नहीं

देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए एक प्रवेश परीक्षा (कॉमन प्लेटफार्म) की व्यवस्था नहीं है। प्रो. कुमार के मुताबिक कुछ राज्यों से इसके लिए सुझाव आए हैं। पर, सबकी अपनी व्यवस्था है। सभी राज्यों के सिलेबस अपग्रेड नहीं हैं। इसलिए अब तक आम राय नहीं बनी है।

उन्होंने कहा कि परीक्षा सुधार को एक्रीडिएशन से जोड़ा गया है। 8-10 विषयों के मॉडल प्रश्न पेपर एआईसीटीई की वेबसाइट पर डाले गए हैं। इसकी जानकारी विश्वविद्यालयों को जाकर दे रहे हैं। पर, उन्हें इसे अपनाने का जोर नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अपनाने वाले जल्द एबीए पा सकेंगे।

प्रो. कुमार ने कहा कि तकनीकी शिक्षा को लेकर राज्यों से प्लान मांगा पर, सही रिस्पांस नहीं आया। इसके बाद इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलकर प्लान छोटी और लंबी अवधि के लिए योजना बनाई गई। आने वाले समय में इसका व्यापक तकनीकी शिक्षा में असर दिखेगा।